फरीदाबाद
# मजदूर समाचार

राहें तलाशने-बनाने के लिए मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

'मजदूर समाचार' की कुछ सामग्री अंग्रेजी में इन्टरनेट पर है। देखें—
< http://faridabad majdoorsamachar.blogspot.in >

डाक पता : मजदूर लाईब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन.आई.टी. फरीदाबाद — 121001

नई सीरीज नम्बर 311 1/— मई 2014

# लहरों द्वारा सामने लाये जा रहे तीखे प्रश्न

मजदूर समाचार के वितरण के दौरान पहले तो सरपंच जैसे दो बुजुर्ग और फिर मोटरसाइकिल पर आये एक हृष्ट-पुष्ट अधेड़ ने सलाह-सी दी : " अखबार यहाँ मत बाँटो। मजदूर बहुत खुश हैं यहाँ। फैक्ट्रियाँ बन्द करवाओगे क्या ?" पढ़ने, लिखने, सोचने, आदान-प्रदान से फैक्ट्रियाँ बन्द हो जायेंगी यह डर कहाँ से आ रहा है?

हमें लगता है कि यह डर टेलरों के बीच घूम रहे एस एम एस की इन पंक्तियों में है : उठे सब के कदम
तर-रम पम-पम
अजी ऐसे गीत गाया करो
हँसो और हँसाया करो।

हमें यह भी लगता है कि यह डर असेम्बली लाइनों पर गुनगुनाई जा रही इन लाइनों में है : तू जिन्दा है
तू जिन्दगी के
गीत पर यकीन कर।

पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली के इर्द-गिर्द का पूरा औद्योगिक क्षेत्र अद्भुत लहरों से ओत-प्रोत है। कम उम्र में ही अनुभवों व विचारों से चेतन हुये लाखों युवक-युवतियाँ नये कदमों, नई भाषा, नई रचनाओं, नये रिश्तों से लहरों को नई ऊर्जा, नई शक्ति दे रहे हैं। ऐसे में इस क्षेत्र ने अनेक प्रकार की पुरानी धारणाओं की सफाई कर दी है और आज की दुनिया में नई सम्भावनाओं का उद्घाटन किया है। अप्रैल अंक में हम ने दो धाराओं को चिन्हित किया था। यहाँ हमारे सम्मुख आये कुछ प्रश्नों को रख रहे हैं जो कि अनगिनत बातचीतों और अनेक कदमों की उपज हैं।

## कोई भी मजदूर हो ही क्यों ?

औद्योगिक क्षेत्रों में यह आजकल इतनी आम बात बन गई है कि इस पर यहाँ चर्चा कुछ मित्रों को शायद अटपटी लगे। फिर भी, कहना तो बनता ही है कि अपना जीवन उसे क्यों समर्पित करें जिसका कोई भविष्य नहीं है। और फिर, अपना जीवन उसे समर्पित क्यों करें जिसकी कोई इज्जत न हो।

मजदूरी में रखा ही क्या है वाली आम बात से डर, भय, विद्वेश, आक्रोश, नाराजगी को हटा कर देखते हैं तो जीवन की एक गहरी सोच और कल्पना मुखर होती है। एक भिन्न जीवन की दस्तक आज साफ-साफ सुनाई देती है और हमारे बीच इतनी क्षमता, योग्यता, बुद्धि है कि प्रयोगों द्वारा भिन्न जीवनों को रूप दिया जा सकता है।

## क्या लगातार उभरती इच्छायें और उठते कदम हर प्रकार की सीमा पर सवाल लिये हैं ?

इस फैले हुये औद्योगिक क्षेत्र में बातचीत में यह बार-बार उभर कर आता है कि हर कार्यस्थल पर टी ब्रेक हो चाहे लन्च ब्रेक, हर ब्रेक चर्चाओं का उफान लिये है। यह अन्तराल बेहद उपजाऊ हैं। अनेक प्रकार की इच्छायें और ढेरों कदम इन से उभरते हैं। तीन साल में, पाँच वर्ष में माँग वाली पुरानी धारणायें आई-गई हो गई हैं। लगातार आँकना, लगातार खींचातान। स्वयं को परखना, समूह की शक्ति को परखना बेरोक चलता है। यह एक हँसी भी लिये है : यह तो मैनेज करने के परे है, कोई भी मैनेजर क्या करे! समझौते जो सीमायें बनाते हैं वो लगातार टूटती रहती हैं। रियायतों के खेलों का लड़खड़ाने लगना। बिचौलियों का असंगत होना।

## सब कुछ तो स्वयं करते हैं, कर सकते हैं तो फिर कोई भी लीडर क्यों ?

"लन्च के बाद फैक्ट्री के अन्दर जाना है अथवा नहीं, कितनी फैक्ट्रियों में एक साथ यह कदम उठाना है, यह सब हम अपने बीच में तय कर लेते हैं।" — ओखला में एक सिलाई कारीगर ने कहा। वहाँ बैठे अन्य कारीगरों ने कहा कि हम स्वयं जब यह करते हैं तब रिजल्ट तुरन्त मिलता है और हमारा आत्मविश्वास बढता है। जबकि, कोई नेता बीच में आ जाता है तो सब गड़बड़ा जाता है और फिर हम में निराशा पैदा होती है। हम जब सब कुछ खुद कर सकते हैं तो फिर अपने लिये निराशा क्यों ढूँढें ?

एक और बातचीत में एक सुन्दर छवि उभरी। " नाइट शिफ्ट में इधर-उधर अकेले सोते वरकर से जनरल मैनेजर बहुत बदतमीजी से पेश आता और एक्शन लेता। हम 108 रात को एक साथ एक जगह सोये। चार मैनेजर आये और इकट्ठे सोते देख चुपचाप चले गये। तीन रोज यही सिलसिला चला। कोई बदतमीजी नहीं, कोई एक्शन नहीं। अन्य सैक्शनों के वरकरों ने भी यह तरीका अपनाया। यह एक परम्परा बन गई।"

## क्या गैर-बराबरी पर हो रहे लगातार आक्रमण नये रिश्तों को बनाने की सूचना है ?

पिछले दो अंकों में हम ने बेक्सटर तथा नपिनो ऑटो एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स फैक्ट्रियों में स्त्री और पुरुष मजदूरों द्वारा फैक्ट्रियों पर से मैनेजमेन्टों का नियन्त्रण हटाने का जिक्र किया था। उस दौरान स्त्री और पुरुष रात-दिन फैक्ट्रियों में रहे जो कि स्वयं में नर-नारी के बीच गैर-बराबरी पर एक उल्लेखनीय आक्रमण है।

कई स्थानों पर परमानेन्ट और टेम्परेरी वरकर अपने बीच की गैर-बराबरी मिटा कर वेतन में बराबर वृद्धि पर जोर दे रहे हैं।

उपरोक्त दोनों मामलों में परम्परा, विरासत को भेदते हुये कुछ नया हो रहा है। (शेष पृष्ठ चार पर)

# नाथने के फेर में क्या से क्या हुआ

पिछले अंक में हम ने बहुत संक्षेप में मजदूरों द्वारा **नपिनो ऑटो एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स** कम्पनी की तीन फैक्ट्रियों पर से मैनेजमेन्ट का कब्जा हटा देने का जिक्र किया था। कुछ बातें मजदूर समाचार के सितम्बर 2013 अंक में हैं और धागों को जोड़ने के प्रयास में कुछ बातें यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।

मई 2010 में एक दिन 800 स्त्री-पुरुष मजदूरों ने प्लॉट 7 सैक्टर-3, आई.एम.टी. मानेसर स्थित फैक्ट्री पर से अचानक मैनेजमेन्ट का कब्जा हटा कर साहबों को चौंका दिया था। चार दिन बाद ही मैनेजमेन्ट फैक्ट्री पर अपना नियन्त्रण पुनः स्थापित कर पाई थी।

तैयारी कर मैनेजमेन्ट ने मई 2011 में मजदूरों पर आक्रमण किया और लगा था कि मजदूरों को गाजर-मूली की तरह काट दिया है। लेकिन यह भ्रम कुछ दिन भी टिक नहीं पाया। जून 2011 में मारुति सुजुकी मानेसर मजदूरों के उभार ने अन्य मैनेजमेन्टों की तरह नपिनो मैनेजमेन्ट में भी असमंजस उत्पन्न किया था। फिर मारुति सुजुकी और अन्य फैक्ट्रियों में अक्टूबर 2011 की मजदूर हलचलों ने नपिनो मैनेजमेन्ट को भी मजदूरों को काबू में रखने के लिये यूनियन की आवश्यकता समझाई थी। और फिर, 18 जुलाई 2012 के मारुति मानेसर उभार ने तो सब मैनेजमेन्टों को बहुत गहरे तक डरा दिया, हिला कर रख दिया था। नपिनो मैनेजमेन्ट ने मई 2011 में नौकरी से निकाले 12 मजदूरों को अगस्त 2012 में वापस ड्युटी पर लिया। यूनियन का रजिस्ट्रेशन।

हालाँकि नपिनो मैनेजमेन्ट ने अपने को मजबूत करने के लिये चटपट चुन कर 100 से ज्यादा मजदूर स्थाई किये लेकिन स्थाई और अस्थाई के बीच विभाजन इस कदर धुँधला रहा कि आरम्भ में यूनियन ने 300 टेम्परेरी वरकरों से भी प्रति मजदूर 100 रुपये प्रतिमाह सदस्यता शुल्क लिया। फिर यूनियन इन अस्थाई मजदूरों को सदस्यता की पर्ची की बजाय यूनियन संघर्ष फण्ड की पर्ची देने लगी पर प्रति मजदूर प्रति माह 100 रुपये लेना जारी रखा। ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों की सक्रियता देखते बनती थी।

यूनियन ने मैनेजमेन्ट को माँग-पत्र दिया। स्थाई मजदूरों और ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की वेतन वृद्धि बराबर होगी की बातें। नवम्बर 2012 में समझौता होना था। मैनेजमेन्ट तथा यूनियन के बीच श्रम विभाग में वार्तायें होती रही और फैक्ट्री में लीडर कहते रहे कि पैसे सब के बराबर बढेंगे, पोजिटिव बातचीत चल रही है। ऐसी लल्लो-पच्चो सुनते-सुनते अगस्त 2013 आ गया। मजदूरों ने दबाव बढाया तो 26 अगस्त से यूनियन ने काली पट्टी शुरू करवाई। श्रम विभाग में 29 अगस्त की वार्ता भी पहले जैसी रही। यूनियन ने 30 अगस्त 2013 को कम्पनी को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया और मजदूरों से कहा कि कम्पनी ने इस बीच समझौता नहीं किया तो यूनियन एक्शन लेगी।

5 दिन की जगह महीना निकल गया,दो महीने निकल गये, 3-4-5-6 महीने निकल गये और यूनियन काले फीतों पर ठहरी रही। मजदूर, विशेषकर ठेकेदारों के जरिये रखे वरकर एक्शन के लिये यूनियन पर दबाव बढाने लगे। ऐसे में सितम्बर 2013 के बाद मजदूरों की मीटिंग करने की यूनियन की हिम्मत नहीं हुई।

2013 की दिवाली के बाद , और खासकरके इस वर्ष जनवरी से तो मजदूरों के फैक्ट्री में यूनियन बॉडी से बार-बार लड़ाई के आसार बनने लगे। फैक्ट्री में यूनियन बॉडी के 12 लीडरों में से 6 नेता कोई काम नहीं करते। अलग-अलग लाइन से जाते मजदूर उन्हें एक्शन के लिये कहते तो लीडर कहते : ''काम करो। प्रोडक्शन पूरा दो।'' मार्च में तो फैक्ट्री में कभी-भी कुछ हो सकता है वाली स्थिति बनी। कुछ शुरू हो जाता तो यूनियन और मैनेजमेन्ट के नियन्त्रण में नहीं आता। आर-पार की बातें, बगावत के लिये तत्पर मजदूर। और, कम्पनी की सैक्टर-8 में खुली नई फैक्ट्री, जिसमें सब मजदूर अस्थाई हैं, वहाँ मजदूर मार्च में मैनेजमेन्ट के नियन्त्रण में नहीं रहे।

तब मजदूरों से बिना किसी प्रकार की चर्चा के, यूनियन ने अचानक 24 मार्च को कदम उठाया। आज की आवश्यकता के अनुसार कदम उठाया। ए, बी, जनरल शिफ्ट के स्त्री व पुरुष मजदूर कम्पनी की गुड़गाँव क्षेत्र की तीन फैक्ट्रियों में दो बज कर 25 मिनट पर बैठ गये। तीनों फैक्ट्रियों पर से मैनेजमेन्ट का कब्जा हटा दिया और यह कदम यूनियन के निर्देश पर उठा। मजदूरों में उत्साह, नये सिरे से जोश, शक-शंका के लिये कोई स्थान नहीं। महिला मजदूरों को दिन-रात फैक्ट्रियों में रहने में कोई झिझक नहीं। स्थाई और अस्थाई में कोई भेद नहीं। कोई गैर-बराबरी नहीं।

फैक्ट्रियों पर से मैनेजमेन्ट का कब्जा हटे चार दिन हो गये तब 28 मार्च को कम्पनी के चेयरमैन-मैनेजिंग डायरेक्टर ने यूनियन लीडरों को बातचीत के लिये दिल्ली बुलाया। शर्तों से इनकार की बात लीडरों ने आ कर फैक्ट्री में बताई। बड़े साहब ने 2 अप्रैल को यूनियन लीडरों को फिर दिल्ली बुलाया। फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजमेन्ट और यूनियन के बीच समझौता वार्ता करना तय हुआ। फैक्ट्री में 2 अप्रैल को लगातार बातचीत और बीच-बीच में लीडर आ कर बोले कि पोजिटिव हो रहा है, घबराना मत, स्थाई और अस्थाई मजदूरों की वेतन वृद्धि बराबर होगी, नपिनो में इतिहास रचा जायेगा। तीन अप्रैल को सुबह मैनेजर आये और बोले कि माल डिस्पैच होने दो, सैटलमेन्ट हो गया है। यूनियन लीडर बोले कि समझौता हो गया है, माल बाहर जाने दो।

दोपहर बाद अन्दर बैठे सब मजदूर गेट पर पहुँचे। लीकेज हुआ। बराबर वेतन वृद्धि की बजाय स्थाई मजदूरों की तीन वर्ष में 8100 रुपये और ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की 3100 रुपये....... कोई भाषण नहीं, लीडरों की समझौता सुनाने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़े से जो समझौते के पक्ष में थे उन से झड़पें शुरू हो गई। इस गैर-बराबरी के खिलाफ अधिकतर मजदूर उबल पड़े। बाहर वाले यूनियन लीडर फैक्ट्री की यूनियन बॉडी के 12 नेताओं को पिटने से बचाने के लिये उन्हें जीप में बैठा कर भागे। समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला एक पिट चुका है। यूनियन के जिला लीडर फैक्ट्री के नजदीक नहीं आये हैं, दूर देवीलाल पार्क में अपने चन्द समर्थकों के साथ मीटिंग करते हैं।

कम्पनी की तीन फैक्ट्रियों में 12 रोज दिन-रात साथ रहे स्त्री-पुरुष मजदूरों में गुस्से के संग-संग सोच-विचार चल रहा है। और, मजदूरों को नाथने चली यूनियन खुद ही चित्त हो गई।

## निमंत्रण

मई में 25 तारीख वाले रविवार को मिलेंगे। सुबह 10 से देर साँय तक अपनी सुविधा अनुसार आप आ सकते हैं। फरीदाबाद में बाटा चौक से थर्मल पावर हाउस होते हुए रास्ता है। ऑटोपिन झुग्गियाँ पाँच-सात मिनट की पैदल दूरी पर हैं।

Ph. 0129-6567014

E-mail<baatein1@yahoo.co.uk>

*✶ अपने अनुभव व विचार मजदूर समाचार में छपवा कर चर्चाओं को और बढाइये। नाम नहीं बताये जाते और अपनी बातें छपवाने के कोई पैसे नहीं लगते। ✶ बाँटने वाले फ्री में यह करते हैं। सड़क पर मजदूर समाचार लेते समय इच्छा हो तो बेझिझक पैसे दें।*

*✶ महीने में एक बार छापते हैं, 12,000 प्रतियाँ निःशुल्क बाँटने का प्रयास करते हैं। चर्चाओं के लिए समय निकालें।*

# कानून कम्पनियों की जेबों में
# मन, मस्तिष्क, हाथों की ताकत मजदूरों में

✶इन बातों को तीन-चार साल हो गये। **आनन्द इन्टरनेशनल-लिलिपुट** फैक्ट्रियों की बात हैं। कम्पनी की कई फैक्ट्रियाँ थी। ऐसे में कमरे में एक फैक्ट्री के 10 टेलर बात करके कदम उठाना तय करते तब यह डर कि कम्पनी की अन्य फैक्ट्रियों में काम चलता रहेगा। दिक्कत होगी, बात बनेगी नहीं। अन्य फैक्ट्रियों के वरकरों से तालमेल जरूरी...... हर जगह कोई न कोई सम्पर्क निकल ही आता। उन फैक्ट्रियों में भी आपस में चर्चायें हो जाती। तय कर लेते। फोन नेटवर्क बन गया था इसलिये मोबाइल फोन से तालमेल हो जाते। तय किये दिन लन्च के बाद फैक्ट्री के अन्दर नहीं जाते। फोन पर अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों को भी बोल देते। उन फैक्ट्रियों में भी लन्च बाद मजदूर फैक्ट्रियों में अन्दर नहीं जाते। सब वरकर डी-3 ओखला फेज-1, दिल्ली स्थित फैक्ट्री व कम्पनी हैड आफिस पर एकत्र हो जाते। अन्दर से मास्टर, मैनेजर बुलाने आते तो पैसे बढाने की बात उठाते। "चलो मशीनों पर बैठो, पैसे बढा देंगे" कहते तो मजदूरों की तरफ से डायरेक्टर को बुलाने और उन से कहलवाने पर जोर होता। एक बार की बात है। एक अफसर ने एक गलत लफ्ज इस्तेमाल किया तो 20-25 मजदूर गेट पर टूट पड़े — गेट ही निकल आया था! एक बन्दा जिसके बारे में प्रचार था कि तीन को गोली मार चुका है, वह धमकाने के अन्दाज में आगे आया तो हजारों मजदूरों में से आवाजें आई : तू है कौन! चल परे हट! डायरेक्टर को बुलाओ। वह बन्दा चुपचाप खिसक गया था। डायरेक्टर आया और पैसे बढाने की बात कही तब कम्पनी की फैक्ट्रियों में काम आरम्भ हुआ था।

✶प्लॉट 4 सैक्टर-3, आई.एम.टी. मानेसर स्थित **जे एन एस इन्सट्रूमेन्ट्स** और **जेय उशिन** फैक्ट्रियों में 10 फरवरी को सुबह 9 बजे की शिफ्ट में दो हजार से ज्यादा महिला मजदूर डेढ-दो घण्टे गेट के अन्दर नहीं गई थी। गेट पर एकत्र महिला मजदूर हरियाणा मुख्य मन्त्री की 1 जनवरी से 8100 रुपये न्यूनतम वेतन की घोषणा पर अमल की बात कर रही थी। आश्वासन दे कर कम्पनी अधिकारी तब अन्दर ले गये थे। महिला मजदूरों ने 12 मार्च को फिर कदम उठाया और 13 मार्च को पुरुष मजदूर भी उनके साथ हो लिये। के डब्लू एस लाइन जिस पर हीरो दुपहियों के पैशन प्रो मॉडल के मीटर बनते हैं वह 12 मार्च को 2 घण्टे ही चली और 13 मार्च को पूरे समय बन्द रही। मजदूरों के कदम का असर प्रेस शॉप, प्रिन्टिंग, मुवमेन्ट लाइन, ऑटो लाइन पर पड़ा। मजदूरों के कदम को विफल करने के लिये 13 मार्च को सुबह 6 वाली बसों को कम्पनी सीधे अन्दर ले गई, इस प्रकार कुछ महिला मजदूरों को जबरन फैक्ट्रियों के अन्दर ले गई। तब 9 बजे वाली बसों की महिला मजदूर बसों को आई.एम.टी. चौक पर ही रुकवा कर बसों से उतर कर पैदल फैक्ट्रियों की तरफ चली। पुरुष मजदूर पैदल पहुँचते हैं और 13 मार्च को सुबह 6 वाली शिफ्ट में वे फैक्ट्रियों के अन्दर गये ही नहीं। कम्पनी 13 को साँय को बोली कि तनखा में एक हजार रुपये बढा देंगे और अब से ओवर टाइम के पैसे सिंगल रेट की बजाय दुगुनी दर से देंगे — काम पर चलो। इस सम्बन्ध में 28 अप्रैल को जे एन एस मजदूरों ने बताया कि कदम उठाने से तनखा में 1000 रुपये बढा दिये हैं और ओवर टाइम का भुगतान डबल रेट से शुरू कर दिया है — पर हाँ, पहले 12 घण्टे ड्युटी में जहाँ कम्पनी 4 घण्टे को ओवर टाइम कहती थी, अब 12 घण्टे की ड्युटी में 3½ घण्टे को ओवर टाइम मानती है।

✶प्लॉट डी-23 ओखला फेज-1, दिल्ली स्थित **रेमियो फैशन** फैक्ट्री में टेलरों की पेमेन्ट 15 दिन में होती है। कम्पनी ने 26 अप्रैल को पैसे देने थे, नहीं दिये। रविवार पड़ गया 27 का और 28 अप्रैल को दोपहर तक पैसे नहीं दिये तो 3 बजे सिलाई कारीगरों ने काम बन्द कर दिया। कम्पनी अधिकारी कुछ नहीं बोले और रात 8 की बजाय 6 बजे टेलरों ने छुट्टी कर ली। अगली सुबह 9½ बजे काम शुरू नहीं किया। डायरेक्टर का सहायक 10½ बजे आया और बोला कि काम शुरू करो, एक बजे से पेमेन्ट हो जायेगी। काम आरम्भ किया, 1½ घण्टे काम किया, पैसे नहीं दिये, फिर काम बन्द कर बैठ गये। साँय 6 बजे पेमेन्ट शुरू की तो पहले उन्हें पैसे देने को कहा जो यहाँ की नौकरी छोड़ गये हैं और दूसरी जगह से छुट्टी कर पेमेन्ट लेने आये थे। पैसे बँटने लगे तब भी काम आरम्भ नहीं किया — पैसे कम थे, समाप्त हो गये, मजदूर रात 8 बजे तक फैक्ट्री में बैठे रहे। तीस अप्रैल को सुबह 9½ काम शुरू नहीं किया। दस बजे पैसे आये। पेमेन्ट में एक कारीगर ने दो घण्टे के पैसे कम पाये। चर्चा। एतराज। कैशियर से खटपट, गार्ड की गलती बताई, उस ने दो घण्टे चढाये नहीं थे। हिसाब ठीक किया गया, 12 बजे तक सब टेलरों को पैसे दे दिये तब काम शुरू किया। फैक्ट्री में फिनिशिंग विभाग में कम्पनी 10 घण्टे को 8 घण्टे के बराबर कहती है। दिल्ली सरकार द्वारा 8 घण्टे के लिये निर्धारित न्यूनतम वेतन को 10 घण्टे काम पर देते हैं। और, मजदूरों को काम करते 10 घण्टे हो जाते हैं उसके बाद के समय को ओवर टाइम कहते हैं। जिसे ओवर टाइम कहते हैं उसका भुगतान भी सिंगल रेट से करते हैं। फिनिशिंग वरकरों को काम करते दो-ढाई महीने हो जाते हैं तब एक महीने की तनखा उन्हें देते हैं।

✶प्लॉट एक्स-28 ओखला फेज-2, दिल्ली स्थित **थीम एक्सपोर्ट** फैक्ट्री में कार्यरत 300 टेलरों की दो कैटेगरी बना रखी हैं — सैलरी वाले और दिहाड़ी वाले। पैसे सब सिलाई कारीगरों को महीने बाद ही दिये जाते हैं और हर महीने मजदूर काम बन्द कर बैठ जाते हैं तब मैनेजमेन्ट तनखा देती है। टेलर 15 तारीख तक इन्तजार करते हैं और 15 को साँय 4 बजे तक पैसे नहीं दिये तो काम बन्द। सब टेलर, सैलरी वाले और दिहाड़ी वाले, मिल कर काम बन्द करते हैं।

✶प्लॉट डी-28 ओखला फेज-1, दिल्ली स्थित **एस एम एस एक्सपोर्ट** फैक्ट्री में दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भी किसी मजदूर को नहीं देते। पचास महिला मजदूरों की तनखा 4000-5000 रुपये। सिलाई कारीगर 170-180 हैं और उन्हें 8 घण्टे के 328 रुपये ही देते हैं। फैक्ट्री में कटिंग, दो फिनिशिंग और प्रोडक्शन में 300 से ज्यादा मजदूर हैं। कम्पनी ने स्वयं एक वरकर भी नहीं रखा है, सब मजदूरों को ठेकेदारों के जरिये रखा है। सुबह 9-9½ से रात 9 तक की एक शिफ्ट है और महिला मजदूरों को सुबह 7 बजे भी बुला लेते हैं। ओवर टाइम का भुगतान कानून अनुसार दुगुनी दर से देने की बजाय पैसे सिंगल रेट से देते हैं। इधर मजदूर मिल कर कदम उठाने के लिये सोच-विचार करते रहे हैं। (फलाँ) दिन लन्च के बाद फैक्ट्री के अन्दर नहीं जायेंगे। सब वरकर बाहर रहेंगे। कोई आगे नहीं होगा। कोई बुरा नहीं बनेगा, कोई टारगेट नहीं बनेगा। किसी नेता को बीच में नहीं आने देंगे। पहलेपहल टेलरों को 8 घण्टे के न्यूनतम वाले 399 रुपये की बात उठा कर अपने को और कम्पनी को आँकेंगे।

---

✶**दिल्ली** में 1.4.2014 से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन

अकुशल श्रमिक : 8554 रुपये

अर्ध-कुशल श्रमिक : 9438 रुपये

कुशल श्रमिक : 10374 रुपये

# नया दौर और पुराने तरीके

पिछले अंक में उपरोक्त शीर्षक से हम ने 39-40 मील पत्थर, एन. एच. 8, नरसिंहपुर , गुड़गाँव स्थित **बजाज मोटर** के स्थाई मजदूरों तथा ठेकेदारों के जरिये रखे वरकरों की बातें कुछ विस्तार से दी थी। इस फैक्ट्री में 2011 और 2012 में परमानेन्ट तथा टेम्परेरी मजदूरों के बीच बनते, बढते अच्छे सम्बन्ध आज के दौर के माफिक फैक्ट्री स्तर पर मजदूर संगठन के उभरने की सम्भावना बढा रहे थे। साथ ही साथ, अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों के संग रिश्ते बनाने में बजाज मोटर मजदूर सक्रिय थे। मैनेजमेन्ट डरी तो थी ही, आगे उसे अधिक बड़ा खतरा नजर आ रहा था। मारुति सुजुकी मानेसर फैक्ट्री में स्थाई मजदूरों, ट्रेनी, अप्रेन्टिस, ठेकेदारों के जरिये रखे मजदूरों के बीच जोड़ों से आज के दौर के माफिक मजदूर संगठन फैक्ट्री स्तर पर उभरा था। और, मारुति सुजुकी मानेसर फैक्ट्री के मजदूर अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों के साथ अच्छे सम्बन्ध बना रहे थे। इस सब ने मारुति सुजुकी कम्पनी के संग अन्य कम्पनियों को हिला कर रख दिया था, हरियाणा सरकार को पसीना ला दिया था, केन्द्र सरकार को चिन्तित कर दिया था।

इधर लगता है कि कम्पनी और सरकार के बीच बजाज मोटर की इस फैक्ट्री को ठण्डा रखने के लिये कदमों पर सहमति बनी। फैक्ट्री में 283 स्थाई मजदूर और 8-9 ठेकेदारों के जरिये रखे 1500 से ज्यादा वरकर कार्यरत थे। फैक्ट्री में स्थाई-अस्थाई मजदूरों को जोड़ने और अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों से सम्बन्ध बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहे एक मजदूर को नौकरी से निकालने के लिये जाल बुना गया। नौकरी से निकाल दिया।

अन्य कई स्थानों की तरह बजाज मोटर की इस फैक्ट्री में भी कानून अनुसार स्थाई मजदूरों का संगठन, यूनियन थी। और, अन्य ऐसे स्थानों की तरह 85 प्रतिशत मजदूर, जो कि अस्थाई थे, कानून के पालन के कारण वे यूनियन के सदस्य नहीं। पुराने तरीके और कानून के ताने-बाने ऐसे अखाड़ों का निर्माण करते हैं जिनमें मैनेजमेन्ट, सरकार, यूनियन के जिला-प्रान्तीय-केन्द्रीय लीडर मजदूरों को थका सकते हैं।

संक्षेप में : निकाले मजदूर को ड्युटी पर रखवाने के लिये दबाव बनाने के लिये यूनियन के बड़े लीडरों ने काम धीमा करने को कहा। फैक्ट्री में स्थाई और अस्थाई मजदूरों ने स्लो डाउन कर दिया। मैनेजमेन्ट ने 24 फरवरी को 15 स्थाई मजदूर सस्पैण्ड और शर्तों पर हस्ताक्षर वाली चाल चली। आपस में अच्छे सम्बन्धों के कारण स्थाई मजदूरों के साथ 1500 अस्थाई मजदूर भी 24 फरवरी को फैक्ट्री के अन्दर नहीं गये। यूनियन नेताओं ने मैनेजमेन्ट के कदम को गैर-कानूनी तालाबन्दी कहा और श्रम विभाग गये। कम्पनी ने मजदूरों द्वारा फैक्ट्री में प्रवेश नहीं करने को गैर-कानूनी हड़ताल कहा और श्रम विभाग गई।

श्रम विभाग में तारीखें। जिला और प्रान्तीय यूनियन लीडर जो यह कर देंगे, वह कर देंगे की बातें करते थे वे नाममात्र की सभा, मीटिंग, चेतावनी के बाद संसदीय चुनाव की आचार संहिता की दुहाई देने लगे। फैक्ट्री के बाहर बैठे कुछ दिन हो गये तब अस्थाई मजदूर इधर-उधर ढूँढ कर काम करने लगे। इस प्रकार 1500 मजदूर दूर होने के बाद पौने तीन सौ स्थाई मजदूर ही गेट पर बैठे रहने लगे। पुलिस 24 फरवरी से ही फैक्ट्री के अन्दर व बाहर लगी थी। मैनेजमेन्ट ने स्टाफ, ट्रेनी, नई भर्ती द्वारा 24 फरवरी से फैक्ट्री में उत्पादन जारी रखा था। बजाज मोटर समूह की अन्य स्थानों पर स्थित 8-10 फैक्ट्रियों में सामान्य काम जारी था। ☞

हरियाणा में संसदीय चुनाव वाली तारीख 10 अप्रैल भी निकल गई। यूनियन के जिला-प्रान्तीय नेताओं की थोथी बातों पर विश्वास करने के लिये मजदूर अब खुद को धोखा भी नहीं दे पा रहे थे। ऐसे में 24 फरवरी से फैक्ट्री गेट के बाहर बैठे स्थाई मजदूरों ने अपने साथियों, फैक्ट्री-स्तर के लीडरों को अप्रैल के अन्तिम सप्ताह में साफ-साफ कह दिया कि पहली मई को 2 बजे तक या तो कुछ कर लो अन्यथा सब मजदूर फैक्ट्री के अन्दर चले जायेंगे।

मजदूरों को थका देने के बाद श्रम विभाग सक्रिय हुआ और 30 अप्रैल को मैनेजमेन्ट-यूनियन समझौता हुआ। निकाले हुये सक्रिय मजदूर के बारे में कोई बात नहीं, निलम्बित 15 में से 4 को 5 मई को ड्युटी पर लेंगे, फिर 20 मई को 4 अन्य सस्पैण्ड को ड्युटी पर लेंगे, 7 निलम्बित की इनक्वायरी होगी और तब तक वे बाहर रहेंगे, 24 फरवरी से 30 अप्रैल तक के कोई पैसे स्थाई मजदूरों को नहीं दिये जायेंगे।

नये दौर में पुराने तरीके मजदूरों के लिये घातक हैं। आज के माफिक कदमों और संगठन स्वरूपों पर चर्चायें, आदान-प्रदान आवश्यक हैं।

# पथरेड़ी तक

राजस्थान में अलवर के पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित **श्रीराम पिस्टन एण्ड रिंग** फैक्ट्री में मजदूरों ने मार्च में, और फिर अप्रैल में फैक्ट्री पर से मैनेजमेन्ट का कब्जा हटाया।

मार्च में 1200 मजदूरों ने पाँच दिन फैक्ट्री पर से मैनेजमेन्ट का कब्जा हटाया। एग्रीमेन्ट द्वारा मैनेजमेन्ट ने अपना नियंत्रण पुनः स्थापित किया पर यह समझौता एक महीना भी नहीं टिका। वरकरों ने 15 अप्रैल को फिर से फैक्ट्री पर से मैनेजमेन्ट का कब्जा हटा दिया।

कम्पनी कोर्ट गई। अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि फैक्ट्री से मजदूरों को बाहर निकालो और मैनेजमेन्ट का कब्जा पुनः स्थापित करो। उच्च पुलिस अधिकारी के मुताबिक 26 अप्रैल को पुलिस ने वॉटर कैनन, आँसू गैस, लाठी चार्ज किया — फिर भी मजदूर नहीं निकले। तब पुलिस ने गोलियाँ चला कर फैक्ट्री खाली करवाई।

## लहरों द्वारा सामने लाये.....( पृष्ठ एक का शेष )

## क्या आज के अनेक कदम माँग के ढाँचे के पार चले गये हैं ?

इस पूरे विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रभावशाली धारा उभरी है जिसे हालात, माँग, रियायत की भाषा में नहीं समझा जा सकता। क्यों नहीं समझा जा सकता? मजदूरों को बेचारे प्रस्तुत करना उन्हें पहले तो हालात का शिकार और फिर माँग तथा रियायत का मोहताज बनाना है। फिर मजदूरों को हालात, माँग, रियायत के पाबन्द घोषित कर उन्हें बेचारे बनाना। यह एक चक्रव्यूह है। और, हाल के वर्षों में इस चक्रव्यूह को मारुति सुजुकी मानेसर मजदूरों ने दोफाड़ किया है। **मजदूर चाहते क्या हैं?** कम्पनी, हरियाणा सरकार, केन्द्र सरकार 2011 में, 2012 में, आज तक समझ नहीं पाई हैं। उनकी घबराहट यहीं से आती है। इसलिये उल्लेखनीय रियायतों के बावजूद विस्फोट हुये तब क्षेत्र में 600 कमाण्डो परमानेन्टली रखे गये हैं, 147 मजदूर आज भी राजनीतिक कैदी हैं।

## क्या यह सारे प्रश्न विश्व में सब के लिये हैं?

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए रौनिजा प्रिन्टर्स फरीदाबाद से मुद्रित किया। **RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73/12-14**
सौरभ लेजर टाइपसैटर्स, बी—551 नेहरु ग्राउंड, फरीदाबाद द्वारा टाइपसैट।